भारत-नेपाल सम्बंध

निकटतम् पडोसी होने के नाते भारत और नेपाल के बीच अद्भुत सम्बंध, मैत्री एवं सहयोग है जिसकी पहचान, मुक्त सीमायें, गहन व्यैक्तिक सम्पर्क, भाईचारा एवं संस्कृति, आदि से है। मुक्त सीमाओं के आर-पार लोगों के मुक्त रूप से भ्रमण करने की एक लम्बी परम्परा रही है। नेपाल के पास 147181 वर्ग कि. मीटर का क्षेत्रफल है और इसकी जनसंख्या 29 मिलियन है। इसकी 1850 कि. मी. से अधिक की सीमा, दक्षिण-पूर्ब एवं पश्चिम में भारत के पाँच प्रान्तों-सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड से मिलती हैं तथा उत्तरी सीमा लोकताँत्रिक गणराज्य चीन के स्वायत्तशासी क्षेत्र तिब्बत से मिलती है।

नेपाल में लगभग 6,00,000 भारतीय/भारतीय मूल के नेपाल नागरिक रह रहे हैं, इनमें नेपाल में लम्बे समय से रह रहे व्यवसायी, व्यापारी समुदाय, व्यावसायिक लोग (चिकित्सकगण, अभियंतागण, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के व्यावसायिक लोग) तथा श्रमिक (निर्माण क्षेत्र में मौसमी आप्रावासित) आदि सम्मिलित हैं।

भारत और नेपाल के बीच नियमित उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान प्रदान की परम्परा को बनाये रखते हुए नेपाल के राष्ट्रपति माननीय डॉ0 राम बरन यादव भारत के एक सरकारी यात्रा पर 24 से 29 दिसम्बर, 2012 की अवधि में आये थे। नेपाल से भारत के लिए की गयी हाल की अन्य यात्राओं में नेपाल के माननीय प्रधान मंत्री डॉ0 बाबू राम भटराई (20 से 23 अक्टूबर, 2011) ,

माननीय प्रधान मंत्री श्री माधव कुमार नेपाल (18 से 22 अगस्त, 2009), माननीय प्रधान मंत्री श्री पुष्प कमल दहल 'प्रचण्ड' (14 से 18 सितम्बर, 2008 और 28 से 30 अप्रैल, 2013 की अवधि में) तथा माननीय पूर्व प्रधान मंत्री श्री शेर बहादुर देऊबा (9 से 14 जून, 2013 की अविध में) और पूर्व प्रधान मंत्री श्री शेर बहादुर देऊबा 9 से 14 जून, 2013 आदि यात्रायें सम्मिलित हैं। भारतीय पक्ष से माननीय विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद नेपाल की एक सद्भावना यात्रा पर 9 जुलाई, 2013 को गये थे। विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह नेपाल की अपनी सरकारी यात्रा पर 14 से 15 सितम्बर, 2013 की अवधि में गयीं थी।

1950 भारत-नेपाल शान्ति एवं मैत्री संधि, वर्तमान में भारत-नेपाल के बीच विद्यमान विशेष सम्बंधों की आधार-शिला है। संधि के प्रावधानों के अन्तर्गत नेपाली नागरिक भारत में भारतीय नागरिकों के बराबर ही, यहाँ की सुविधाओं और अवसरों का अद्वितीय लाभ उठा रहे है। नेपाल के चारों ओर से घिरे हुए देश होने के कारण जो हानि हो रही थी इस संधि ने उसे उससे बाहर निकाल लिया हैं। अधिक समय से नेपाल की अनेक सरकारों ने संधि के नवीनीकरण के मुद्दे को उठाया था। भारत कहता आ रहा है, कि वह सभी द्विपक्षीय व्यवस्थाओं का द्विपक्षीय सम्बंधों को अधिक मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से परीक्षण करने का इच्छुक है। नेपाल पक्ष से किसी भी प्रकार के विशेष आसन्न सुझाव नहीं प्राप्त हुए हैं।

12 बिंदुओं के साथ, सात दलों के गठबंधन (एस पी ए) और माओवादियों के बीच सहमति नई-दिल्ली में नवम्बर, 2005 में हुई थी। भारत सरकार नवम्बर 2006, के ऐतिहासिक विस्तारित शान्ति समझौते में प्रावधान किये गये योजनाओं का स्वागत करती है, जिसमें नेपाल में राजनैतिक

स्थिरता को शान्तिपूर्ण समझौते और लोकताँत्रिक प्रक्रिया को सम्मिलित करते हुए, समाधान का प्रावधान है। भारत ने लगातार, नेपाल सरकार और वहाँ के लोगों की आवश्यकता की अनिवार्यता के भाव के प्रति ध्यान दिया है और शान्ति प्रक्रिया की सफलता सुनिश्चित करने के लिए बहु-दलीय लोकतंत्र को चुनी हुई संविधान सभा द्वारा निर्मित नये संविधान के माध्यम से संस्थागत स्वरूप प्रदान करने का पक्षधर है।

मंत्री परिषद के अध्यक्ष श्री खिल राज रेगमी के नेतृत्व में अंतरिम चुनाव सरकार के गठन (आई ई जी) के साथ ही 14 मार्च, 2013 को मई, 2012 में संविधान सभा के भंग करने के समय से ही नेपाल में व्याप्त राजनैतिक अनिश्चितता की लम्बी अवधि का अंत हो गया था। राजनैतिक दलों और चुनाव आयोग के सहयोग से 'आई ई जी' ने द्वितीय का संचालन 19 नवम्बर, 2013 को सफलतापूर्वक किया गया था। भारत ने नेपाल के संविधान सभा और संसद के चुनावों की अवधि में नेपाल के चुनाव आयोग और नेपाल के पुलिस अभिकरणों द्वारा उपयोग में लाने के लिए 56.12 करोड़ रुपयों की लागत से 764 वाहन प्रदान किया था। भारत सरकार ने नेपाल सेना को समर्थन प्रदान करने के लिए वाहन एवं अन्य संचालन तंत्र प्रदान करने के अतिरिक्त चुनावों के उद्देश्य से उधारी के आधार पर दो हेलिकॉप्टर भी प्रदान किये हैं।

भारत द्वारा नेपाल सरकार (जी ओ एन) के विकास प्रयासों में मौलिक ढांचा, स्वास्थ्य, ग्रामीण एवं समुदाय विकास, शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों में विभिन्न विकास परियोजनाओं की वचनबद्धता के माध्यम से योगदान किया जाता है। वर्ष, 2012-13 की अवधि में ''नेपाल को सहायता'' के अंतर्गत 300 करोड़ की बजट अनुदान सहायता प्रदान की गयी थी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने नेपाल में

चल रही शांति प्रक्रिया में पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान किया है। भारत द्वारा नेपाल को प्रदान की गयी सहायता का संपूर्ण घनत्व 4000 करोड़ रुपयों से अधिक का है जिसमें लघु विकास परियोजनायें, भारत के राजदूतावास द्वारा प्रदान की गयी योजनाओं जो स्थानीय जनसंख्या के द्वारा चिंहित किये गये क्षेत्रों में जनसाधारण के स्तर की विकास सहायता प्रदान करती हैं। यह वर्तमान में 425 परियोजनाओं पर 500 करोड़ रुपये का व्यय कर रही हैं। भारत द्वारा नेपाल के क्षमता निर्माण एवं मानव संसाधन विकास के प्रयासों में सहायता प्रदान करने के एक हिस्से के रूप में लगभग 2200 छात्रवृत्तियां नेपाली छात्रों को भारत और नेपाल में स्थित शैक्षिक संस्थानों द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष प्रदान की जाती हैं।

भारत लगातार नेपाल का विशालतम् व्यापार भागीदार, विदेशी निवेश का विशालतम् स्रोत और पर्यटकों के आगमन का विशालतम् स्रोत बना हुआ है। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष, 2009 में हस्ताक्षरित संशोधित व्यापार संधि से पुन: संवेग प्राप्त हुआ है जिसमें नेपाल द्वारा भारतीय बाजारों में अपनी व्यापक पहुॅच बनाने की अनुमति के प्रावधान हैं। जुलाई, 2013 में समाप्त हुए राजस्व वर्ष के लिए नेपाली ऑकड़ों के अनुसार नेपाल का भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार 26126.9 करोड़ रुपयों का था जो इसके कुल विदेश व्यापार का 66 प्रतिशत है। भारत और नेपाल के बीच एक संक्रमण संधि विद्यमान है जो एक दूसरे को पारस्परिक रूप से सहमत मार्गों और तौर-तरीकों के माध्यम से अधिकार क्षेत्रों में संक्रमण अधिकार प्रदान करती है। संक्रमण संधि का नवीनीकरण 5 जनवरी, 2013 को 7 वर्षों के लिए किया गया है। दोनों देशों द्वारा एक रेल सेवा समझौता (आर एस ए) और एक संशोधित विमान सेवा समझौता (ए एस ए) को द्विपक्षीय

संबद्धता के विस्तार हेतु अंतिम रूप दिया गया है। भारत, नेपाल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विशालतम् स्रोत भी बना हुआ है और 525 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परियोजनाओं के साथ नेपाल में 2175.5 करोड़ रुपयों की राशि के भारतीय निवेश हुए हैं। नेपाल में हुए कुल विदेशी निवेश में 46 प्रतिशत भारत के खाते में है। अक्टूबर-नवम्बर, 2011 की अवधि में दोनों देशों ने द्विपक्षीय निवेश संरक्षण एवं संवर्धन समझौते (बी आई पी पी ए) और दोहरे कर से बचने के समझौते (डी टी ए ए) को अंतिम रूप दिया है जिसमें नेपाल में भारतीय निवेश विस्तार के लिए कानूनी संरचना और दोनों अर्थ व्यवस्थाओं में और अधिक समन्वय स्थापित करने की प्रावधान हैं।

भारत ने नेपाल सेना (एन ए) को उपकरणों एवं प्रशिक्षण के प्रावधानों के माध्यम से आधुनिक बनाने के लिए सहायता प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत के विभिन्न सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए लगभग 180 प्रशिक्षण स्लाट प्रति वर्ष नेपाल सेना के अधिकरियों के प्रशिक्षण हेतु भारत, नेपाल को प्रदान करता है। भारत के सेना प्रमुख को नेपाल में मानद जनरल का रैंक प्रदान किया गया है और प्रत्युत्तर में भारत ने नेपाल सेना प्रमुख को उसी सम्मान से अलंकृत किया है। भारत ने अपने सैन्य बलों में नेपाली लोगों को सैनिक के रूप में पाकर सदैव गर्व का अनुभव किया है और उनके जीवन के संध्याकाल में उनकी भली-भाँति देख-भाल को सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया है। आज की तिथि में 1.26 लाख से अधिक हमारे पूर्व सैनिक नेपाल में रह रहे हैं। वर्ष, 2012-13 की अवधि में नेपाल में रह रहे भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिकों को 1387 करोड़ रुपये की पेंशन राशि का भुगतान किया गया है। भारत सरकार ने हर सम्भव प्रयासों से यह सुनिश्चित किया है कि हमारे पूर्व सैनिकों, उनके

परिवारों और उन पर आश्रितों की सर्वोत्तम सम्भव ढंग से देख-भाल हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने "भारतीय पूर्व सैनिक कल्याण संगठन नेपाल (आई ई डब्लू ओ एन)" की नेपाल में स्थापना की है। भूतपूर्व सैनिकों अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई सी एच एस) का नेपाल में शुभारंभ वर्ष, 2012 की अवधि में हुआ था जिसके माध्यम से नेपाल में रह रहे नेपाली मूल के पूर्व भारतीय सैनिकों और उन पर आश्रित परिजनों को नेपाल के अंदर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी। ई सी एच एस लाभार्थियों के पास भारत में सरकारी पैनल में सम्मिलित निजी चिकित्सालयों में भी चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का विकल्प है।

भारत और नेपाल के बीच जल संसाधन क्षेत्र में सहयोग की व्यापक संभावनायें विद्यमान हैं। नेपाल के पास 43000 मेगा वाट पन विद्युत ऊर्जा की क्षमता विद्यमान है जो आर्थिक दृष्टि से व्यवहार और तकनीकी दृष्टि से साध्य पाया गया है। यद्यपि प्रमुख परियोजनायें आर्थिक क्षेत्र से बाहर होने के कारण शुरु नहीं हो सकी हैं। विडम्बना यह है कि भारत, नेपाल को उसकी सम्पूर्ण ऊर्जा का निर्यात करता है। दोनों देशों द्वारा इस क्षेत्र के सहयोग के महत्व को स्वीकार किया है और मंत्रिस्तरीय एक त्रिस्तरीय द्विपक्षीय यांत्रिकी (जल संसाधन पर संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग-जे एम सी डब्ल्यू आर) की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जल संसाधन पर गठित संयुक्त समिति (जे सी डब्ल्यू आर) और तकनीकी (संयुक्त स्थायी तकनीकी समिति-जे एस टी सी) के सचिव महोदय द्वारा जल से संबंधित मुद्दों में सहयोग के संपूर्ण सप्तक का प्रबंधन किया जाता है।

मुक्त सीमा से जुडे पारस्परिक सुरक्षा के सरोकारों में सहयोग से जुडे मुद्दे, नेपाल के साथ हमारे सम्बंधों का प्रतीक है। नेपाल पक्ष ने विभिन्न स्तरों पर आश्वासन दिया है, कि वह अपने क्षेत्र में भारत के विरुद्ध किसी भी प्रकार की गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं देगा। सीमापार अपराध सहित सुरक्षा से जुडे मुद्दों के समाधान हेतु सीमा से लगे जनपदों और उनके बीच प्रभावशाली संचार सम्बद्धता तथा सूचना के आदान-प्रदान की सुविधा की स्थापना के लिए एक द्विपक्षीय याँत्रिकी विद्यमान है। साझे सीमा पार सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत ने कानूनी संरचना के सशक्तीकरण की आवश्यकता पर बारम्बार जोर दिया है। भारत ने नेपाल में सुरक्षा तंत्र के लिए मूल-भूत ढाँचे, क्षमता निर्माण, उपकरण एवं मानव संसाधन के प्रशिक्षण आदि के विकास में उदारता पूर्ण सहायता भी प्रदान की है।

एक संयुक्त तकनीकी समिति (जे टी सी) भारत और नेपाल के महासर्वेक्षकों के नेतृत्व में संयुक्त रूप से तैयार किये गये और शुरु किये गये भारत-नेपाल सीमा (दिसम्बर 2007) के पट्टी नक्शे का 96 प्रतिशत तैयार कर लिया गया है। इन पट्टी नक्शों के सर्वोच्च स्तरीय प्रमाणन की प्रतीक्षा की जा रही है। नेपाल में सीमा की स्थिति को हाल में कुछ राजनैतिक दृष्टि से प्रेरित लोगों ने प्रतिकूल दिशा में प्रस्तुत करने का प्रयास, भारतीय कब्जे की घटनाओं का आरोप लगाते हुए किया गया था। यद्यपि इस विषय को नेपाल सरकार द्वारा औपचारिक रूप से संज्ञान में नहीं लिया गया था। भारत ने पट्टी नक्शे पर शीघ्रातिशीघ्र हस्ताक्षर किये जाने पर जोर दिया था ताकि सीमा पर लगाये जाने वाले स्तम्भों का कार्य जहाँ वे अपने स्थान से हट गये हैं और जहाँ क्षतिग्रस्त हो गये हैं, वहाँ

मरम्मत करने का कार्य शुरु किया जा सके। नेपाल ने अवगत कराया है कि पट्टी नक्शे पर हस्ताक्षर किये जाने पर राजनैतिक सर्वानुमति निर्मित की जा रही है।

नेपाल में स्थित भारतीय मिशन/चौकियों ने संस्कृति, कला, प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं संचार माध्यमों के क्षेत्र में जन-जन के बीच संपर्कों के संवर्धनार्थ अनेका प्रकार के आयोजन करते रहते हैं। इनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, कार्यशालायें, नेपाल के विभान स्थानीय संगठनों के साथ भागीदारी में आयोजित समारोह तथा सम्मेलन और हिन्दी में आयोजित गोष्ठियां आदि सम्मिलित हैं। भारतीय संस्कृति एवं द्विपक्षीय संबंधों का संवर्धन कर रहे नेपाल के अनेका संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। नेपाल के संपादकों, पत्रकारों एवं विशेषज्ञों के लिए भारत की यात्रा और अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए भी भारत में उपलब्ध व्यवस्था को औपचारिक स्वरूप प्रदान किया जा रहा है।

*****

दिसम्बर, 2013